जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 207 प्रभात बीकानेर, गुरूवार 19 फरवरी, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे

खड़गे, शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, अठावले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होगा

- चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6 तथा बिहार व बंगाल म 5-5 सीटों पर चुनाव होंगे।
- इनके अलावा ओडिशा में 5, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व हरियाणा में 2-2 तथा हिमाचल में एक सीट पर राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे।
- महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताक, 85 वर्षीय शरद पवार ने पहले यह घोषणा की थी कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर शिव सेना के संजय राउत के अनुसार, उन्होंने अब राज्यसभा के एक और कार्यकाल के लिए इच्छा जताई है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। चुनाव आयोग ने बुधवार सुबह कहा कि अप्रैल में खाली होने वाली 37 राज्यसभा सीटों के लिए 10 राज्यों में16 मार्च को चुनाव होंगे।

इनमें से सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र (7) और तमिलनाडु (6) में हैं, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल में पांच-पांच सीटें खाली होंगी। इनके अलावा, ओडिशा में चार सीटें, असम में तीन सीटें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दो-दो सीटें और हिमाचल प्रदेश में एक सीट खाली होगी।

इसके साथ ही, सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिससे राज्यसभा में राजनीतिक समीकरण और मुकाबले की स्थिति बदल सकती है।

इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (कर्नाटक), एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और महाराष्ट्र से रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख रामदास अठावले शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है।

शिव सेना के संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता 85 वर्षीय शरद पवार ने एक और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।

पवार पहले, अपनी उम्र का हवाला देते हुए, कह चुके थे कि वह आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। 50 से ज्यादा साल के राजनीतिक करियर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पवार 14 चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जीते हैं।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (बिहार) का कार्यकाल भी खत्म हो जायेगा। राज्यसभा सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। इसमें सीटों का बंटवारा हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है।

मतदान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। इसलिए हर पार्टी के चुने हुए सांसदों एव विधायकों की संख्या इसमें महत्वपूर्ण होती है। किसी राज्य में एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, इसके लिए एक तय फार्मूला होता है। पिछले साल अगस्त में, भाजपा के राज्यसभा सांसदों की संख्या 2022 के बाद पहली बार 100 से ज्यादा हो गई थी। इससे सत्तारूढ़ पार्टी को दोनों सदनों में नियंत्रण मजबूत करने और अपने विधेयकों को पास कराने में मदद मिली। इन सीटों के लिए पिछला चुनाव 2020 में हुआ था, जब असम, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भाजपा और उसके सहयोगी दल मजबूत स्थिति में थे। महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस के साथ उस समय की संयुक्त शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सीटें बांटी थीं।

तमिलनाडु में डीएमके ने ज्यादातर सीटें जीती थीं, जबकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में क्रमशः तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल बड़ी विजेता पार्टियां रहीं थीं।

एस.के. आईटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली

जयपुर, 18 फरवरी। जगतपुरा स्थित स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान (एसकेआईटी) कॉलेज को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन को धमकी भरा ई-मेल प्राप्त होते ही एहतियातन पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया। छात्र-छात्राओं और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालकर कॉलेज गेट के बाहर एकत्र किया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और बम निरोधक दस्ता सहित, अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

- पूरे कैम्पस को खाली कराकर पुलिस, दमकल व बम निरोधक दस्ते सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बारीकी से जाँच की।

ई-मेल में दावा किया गया कि कॉलेज परिसर में आरडीएक्स से बने बम लगाए गए हैं और निर्धारित समय पर विस्फोट किया जाएगा। संदेश में खुद को 'बालूचोटन टाइगर्स डीएमके आईटी विंग' बताते हुए 11:45 बजे विस्फोट की धमकी दी गई। साथ ही, भड़काऊ और आपत्तिजनक बातें भी लिखी गईं।

गलगोटिया के चीनी रोबोट ने भाजपा नेतृत्व को परेशानी में डाला

विपक्ष के नेताओं ने इस घटना को लेकर केन्द्र सरकार के ''मेक इन इंडिया'' के दावे की आलोचना की

- गलगोटिया विश्वविद्यालय ने जिस रोबोट को खुद की प्रयोगशाला में बना हुआ दिखाकर एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शित किया था, उसे चीन की कंपनी यूनीट्री, भारत में 2-3 लाख रूपए में ऑनलाइन बेचती है।
- विवाद सामने आने के बाद समिट में गलगोटिया विश्वविद्यालय के स्टॉल की लाइट काट दी गई और उन्हें तुरंत एक्सपो एरिया खाली करने के निर्देश दिए गए।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इस समय चल रहे ''इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट'' में अपने सेंटर ऑफ एक्सलैंस द्वारा विकसित बताए गए एक चीनी रोबोटिक कुत्ते को प्रदर्शित करके एक बुरे विवाद में फंस गई है।

इस घटना से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी समेत, कई नेताओं ने केन्द्र सरकार के ''मेक इन इंडिया'' दावे की आलोचना की है और यूनिवर्सिटी के भाजपा नेतृत्व के साथ मजबूत रिश्तों पर सवाल उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व में यूनिवर्सिटी के चांसलर सुनील गलगोटिया को ''डी-क्यू आईसीटी अवॉर्ड'' दे चुके हैं और उन्होंने शिक्षा व वैश्विक सहयोग में उनके योगदान की सराहना की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूनिवर्सिटी की लगातार तारीफ करते हुए इसे ''उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात'' बताया है और राज्य को ''नॉलेज हब'' बनाने में इसकी भूमिका को सराहा है। यूनिवर्सिटी ने सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को भी जोर-शोर से बढ़ावा दिया है।

''ओरायन'' नाम का उक्त रोबोट दरअसल चीनी कंपनी यूनीट्री का बाज़ार में उपलब्ध एक मॉडल है, जो भारत में ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपये के बीच बेचा जा रहा है।

इस रोबोटिक कुत्ते का वीडियो वायरल होने और इंटरनेट पर इसे चीनी प्रॉडक्ट के तौर पर पहचाने जाने के बाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफीनामा जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यह उत्पाद यूनीट्री से खरीदा गया था और इसे केवल छात्रों के सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

बताया गया है कि समिट में चीनी रोबेटिक कुत्ते के प्रदर्शन को लेकर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल का बिजली कनैक्शन भी काट दिया गया। यह कार्रवाई उन्हें एक्सपो क्षेत्र खाली करने के लिए कहे जाने के कुछ मिनट बाद हुई।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक और दावे को लेकर सोशल मीडिया पर सवालों के घेरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि उसके ग्रेटर नोएडा कैंपस के स्टाफ और छात्रों ने स्क्रैच से एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

परिवर्तन रथयात्रा की रणनीति अपना रही है भाजपा प.बंगाल में

राज्य के विभिन्न भागों में 1 मार्च से 10 मार्च के बीच नौ परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी

- भाजपा के प.बंगाल के प्रमुख नेता सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि परिवर्तन यात्राओं से अन्य राज्यों में परिवर्तन आया था, इसलिए बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए हम यहाँ यात्राएं आयोजित कर रहे हैं।
- यात्रा प्रारंभ होने के कार्यक्रम में अध्यक्ष नितिन नबीन, केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री फड़नवीस व स्मृति ईरानी भाग लेंगे। यात्रा की समापन रैली में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और राज्य के अलग-अलग हिस्सों से नौ परिवर्तन रथ यात्राएं शुरू करने की योजना घोषित की है। यह भाजपा के वर्ष 2021 के चुनाव अभियान जैसा ही है।

यात्रा का पहला चरण 1 मार्च को कूचबिहार साउथ, कृष्णानगर साउथ, गढ़बेता और रायडीघी कुल्टी से शुरू होगा।

दूसरा चरण 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखाली, हसन और आमता से शुरू होगा।

होली के मौके पर 3 और 4 मार्च को कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अभियान 5 मार्च से फिर शुरू होगा।

5 से 10 मार्च के बीच, भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेगी। इस दौरान कुल 60 बड़ी जनसभाएं और 300 से ज्यादा छोटी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी।

बंगाल भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी ने कहा, ''यह रथ यात्रा नहीं, बल्कि परिवर्तन यात्रा है। इसे बंगाल में बदलाव लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो चुका है, इसलिए हम इसे बंगाल में भी कर रहे हैं।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली समापन रैली में शामिल होंगे।

यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसओजी ने 10 हजार के इनामी परीक्षार्थी को कोलकाता में पकड़ा

जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट गैंग के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दबिश देकर दस हजार के इनामी डमी परीक्षार्थी प्रिन्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा एमबीबीएस फोर्थ ईयर का छात्र है, जो चंद रुपयों के लालच में सलाखों के पीछे पहुँच गया है।

- एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के छात्र प्रिंस ने सांचोर निवासी मनोहर बिश्नोई का डमी बनकर परीक्षा दी थी

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खालिदा ज़िया के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं बांग्लादेश के एकमात्र हिन्दू मंत्री रॉय चौधरी

निताई रॉय चौधरी का मानना है कि शेख हसीना व अवामी लीग ने बांग्लादेश में सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया

- रॉय चौधरी का दावा है कि यदि केस स्टडी की जाए तो स्पष्ट नज़र आएगा कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग देश में हो रही हर सांप्रदायिक हिंसा में शामिल है।
- रॉय चौधरी के तीन बच्चे हैं। उनकी पुत्री निपुन रॉय चौधरी सक्रिय बीएनपी नेता हैं तथा उनके पति ज्ञानेश्वर चंदन रॉय बीएनपी के टिकट से हाल ही चुनाव जीते हैं। उनका पुत्र देबाशीष रॉय चौधरी बांग्लादेश हाई कोर्ट के जज हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। तारिक रहमान की कैबिनेट में शामिल किए गए 50 मंत्रियों में निताई रॉय चौधरी इकलौते हिंदू मंत्री हैं, जिन्होंने शपथ ली।

निताई रॉय चौधरी बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनेता और वकील हैं और वर्तमान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष हैं। 12 फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में उन्होंने मगुरा-2 सीट से जीत हासिल की और जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को हराया।

उन्होंने पहले, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं खालिदा जिया (जो रहमान की मां भी हैं) के वरिष्ठ सलाहकार के रुप में काम किया है।

7 जनवरी 1949 को मगुरा जिले के मोहम्मदपुर के हटबरिया गांव में जन्मे रॉय चौधरी ने अपनी स्कूली शिक्षा आलोकदिया पुखुरिया हाई स्कूल से पूरी की और उसके बाद मगुरा गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक किया। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और ढाका विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की।

उनका संसदीय करियर 1988 में शुरू हुआ, जब वे मगुरा-2 सीट से जातीय संसद के लिए चुने गए। उन्होंने सितंबर 1990 में लगभग तीन महीने तक युवा और खेल मंत्री के रूप में भी काम किया। उस समय देश में हुसैन मुहम्मद इरशाद की सरकार थी। इरशाद शासन के पतन के बाद वे बीएनपी में शामिल हो गए और बाद में पार्टी के उपाध्यक्ष बने।

रॉय चौधरी शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के खुले आलोचक रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर एक ऐसा ''फासीवादी शासन'' बनाने का आरोप लगाया, जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया और सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया।

सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता जताते हुए रॉय चौधरी ने कहा कि 2001 में जब बीएनपी-जमात गठबंधन सत्ता में आया था, तब हिंदुओं पर ''कुछ अलग-थलग हमले'' हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 18 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को यहां भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उद्घाटन समारोह सुबह लगभग 9:40 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई शीर्ष उद्योगपति शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य वैश्विक नेताओं के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे और विभिन्न देशों के पवेलियन देखेंगे।

- समारोह में प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई शीर्ष उद्योगपति शामिल होंगे।

दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने रील के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति रद्द की

अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ नियुक्ति प्रक्रिया पुनः शुरू करें, जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव को भी शामिल किया जाए

- अदालत ने कहा कि रील में राज्य सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है और यह केन्द्र व राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एवं इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) के प्रबंध निदेशक के पद पर बृजेश दीक्षित की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष व भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव को नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश देते हुए चयन प्रक्रिया में राज्य के मुख्य सचिव को भी शामिल करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश पुरुषोत्तम नारायण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

इस मामले में याचिकाकर्ता पुरूषोत्तम नारायण शर्मा की ओर से अधिवक्ता तनवीन अहमद ने अदालत में गुहार की थी कि रील के नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में तय नियम-कायदों की पालना नहीं की गई, जैसे कि चयन बोर्ड में प्रदेश के मुख्य सचिव को शामिल नहीं किया। इसके विरोध में भारत सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. डी. रस्तोगी ने अदालत को कहा कि यह रिट याचिका इसलिए खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता को यह प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट में दायर नहीं करना चाहिए था। याचिकाकर्ता को सेंट्रल एड्रमिनिट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सी.ए.टी.) याचिका दायर करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता ने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने याचिका दायर कर दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रस्तोगी ने अदालत के समक्ष कई दलीलें दी पेश कीं, जिनमें उन्होंने कहा कि रील में रीको की 49 प्रतिशत भागीदारी है, जबकि 51 फीसदी हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में रीको को राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की इकाई नहीं माना जा सकता। परंतु अदालत के समक्ष जिरह के दौरान यह तथ्य भी स्पष्ट हो गया कि रीको की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने ''रीको इंडस्ट्रियल एरियाज़ एक्ट-1999'' पारित किया था। इसी अधिनियम की धारा-16 के तहत रीको के तमाम अधिकारी-कर्मचारी सरकारी कार्मिक माने जाते हैं।

हैरानी की बात है कि जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि रील की वेबसाइट पर भी अंकित है कि उसे भारत सरकार ''मिनी रत्न'' मानती है और यह केन्द्र व राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इस दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि रील का चेयरमैन भी रीको का प्रबंध निदेशक है। रीको में चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार ही करती है। इसलिए इस तर्क को नहीं नकारा जा सकता कि रीको की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है।

इन सभी तथ्यों को सामने रखते हुए अदालत ने कहा कि रील में राज्य सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है और यह केन्द्र व राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम ही है। रीको का प्रबंध निदेशक पार्ट टाइम निदेशक होने के नाते रील का चैयरमेन है और रीको का संचालन राज्य सरकार करती है। अदालत ने अपने आदेश में यह तथ्य भी दर्ज किया है कि केन्द्र सरकार की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या पत्र पेश नहीं किया गया है, ऑ जिससे यह स्पष्ट होता हो कि चयन प्रक्रिया में मुख्य सचिव को शामिल किया गया हो। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भले ही नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लिया है, परंतु न तो उसे, और न ही आमजन को यह जानकारी दी गई थी कि चयनप्रक्रिया के लिये बोर्ड का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उसने किसी भी उम्मीदवार का बायोडाटा भी देखा हो। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन उम्मीदवार किस वजह से शॉर्ट लिस्ट किया गया और कौन बाहर किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में रमजान का चांद नज़र आया, आज पहला रोज़ा

नई दिल्ली, 18 फरवरी। रमज़ान-उल-मुबारक महीने का चांद आज बुधवार को दिखाई देने का ऐलान किया गया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में सुबह से ही मौसम खराब होने की वजह से चांद को लेकर पहले से ही असंमजस की स्थिति थी और चांद निकलने की सूचना नहीं मिली है। इस बीच देश के कई भागों में चांद नजर आने की सूचना मिली। इसके बाद जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने चांद निकलने का ऐलान किया।

- जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने चांद निकलने का ऐलान करते हुए कहा है कि 19 फरवरी को रमज़ान का पहला रोज़ा रखा जाएगा।